Film Entitled "Emergency—the Nightmare"

4209. SHRI BHAGAT RAM : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether the Information Minister of West Bengal had requested him to personally view the films "Emergency—the Nightmare" to judge for himself if the regional Censor Board's objections were tenable ;

(b) whether he has also received a letter from Information Minister of West Bengal and if so, the contents of the same; and

(c) what is the reaction of Government about the points raised by the West Bengal Government ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) and (b). Yes, Sir. The Information Minister of West Bengal has requested the Central Government to expedite its decision.

(c) The matter is receiving attention.

Exhibition of Films on Family Planning in Rural Areas

4210. SHRI R. KOLANTHAIVELU : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state the reasons way the field Publicity Officer despite repeated requests by many persons including Member of Parliament, is averse to come to rural areas like Irugaloore in Salem District, Tamil Nadu to show films on Family Planning, Health care, for the benefit of weaker sections ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : The Field Publicity Unit at Salem which covers Salem and Dharmapuri districts is faced with an unsurmountable task of covering an area of about 18,286 square kilometres with a population of over 46·7 lakh in about 2000 villages and 50 towns. It is, therefore, not possible for it to cover each and every area within its jurisdiction in every year, though every efforts is made to cover as many areas as possible, particularly the rural areas.

कार्यालयों में चपरासियों के पदों का भरा जाना

4211. **श्री श्याम लाल धुर्वे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में गत तीन वर्षों में पृथक्-पृथक् कितने चपरासी सेवानिवृत हुए हैं और कितने पदोन्नत हुए हैं ;

(ख) क्या इससे रिक्त हुए स्थान सरकार ने भर दिए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जब अन्य पदों के लिए नियुक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तब चपरासियों की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण हैं और क्या इस मामले की समीक्षा करने का उन्होंने कोई आश्वासन दिया है और यह आश्वासन कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० बी० पाटिल) : (क) तथा (ख). कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के पास सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) चपरासियों के अभिनियोजन की वर्तमान पद्धति की समीक्षा करने के विचार से जून 1976 में चपरासियों के रिक्त पदों के भरने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । हालांकि पुनरीक्षा किये जाने के लिए सदन को कोई आश्वासन नहीं दिया गया था परन्तु 2–4–78 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 702 के उत्तर में यह बताया गया था कि चपरासियों के अभि-नियोजन से सम्बन्धित समस्त नीति की पुनरीक्षा की जा रही है । पुनरीक्षा के शीघ्र ही पूरा हो जाने की सम्भावना है ।